भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3935

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के पूरा होने में विलंब

3935. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1972 में शुरू की गई उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग से अपेक्षित स्वीकृति में देरी होने के कारण रोक दिया गया था।

अगस्त, 2017 में, केंद्र सरकार ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था। हालांकि, अनेक कारणों जैसे झारखंड सरकार के वन विभाग से अपेक्षित स्वीकृति मिलने में लगने वाला समय, बांध स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए गए आंदोलन और बिहार के हिस्से में किए जाने वाले कार्यों की सहमति हासिल करने में बिहार सरकार को लगे समय के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है।

केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2023 में 2430.76 करोड़ रुपए (केंद्रीय हिस्सा: 1,836.41 करोड़ रुपए) की संशोधित लागत से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था। इसके लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 771.04 करोड़ रुपये की राशि अब तक जारी की गई है। अक्टूबर, 2023 में परियोजना के अनुमोदन के दौरान निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति और सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति जिसमें और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, बिहार और झारखंड दोनों राज्य सरकारों के और वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के सदस्य हैं, के द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।

*****